affected by the drought.Farmers belonging to the major agricultural districts of Idukki, Wayanad, Palakkad and Thrissur have suffered significant losses. The harsh drought has resulted in partial or complete losses of both food and cash crops. It is learnt that Government of Kerala has approached the Central Government for additional funds to address the situation and support the affected farmers.

In this context, I appeal to the Central Government to grant a special financial package for the revival of agricultural sector in the state. It is requested to issue directions to Banks to write off the agricultural loans of the farmers whose crops have been destroyed. I further urge the Government to provide special financial assistance to the people of Wayanad for compensating the losses in agriculture and livestock. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Shrimati Jebi Mather Hisham: Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Anil Kumar Yadav Mandali (Telangana), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri Muzibulla Khan (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala).

Dr. Fauzia Khan is not present. Now, Dr. Sikander Kumar.

Concern over quality of food and hygiene provided by Railways during travel

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान भारतीय रेलवे, जिसको देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज भी ट्रेन से सफर करना हर भारतीय के जीवन का हिस्सा है। रेलवे द्वारा सफर के दौरान बहुत से ट्रेनों मे खाने की सुविधा भी दी जाती है। रेलवे द्वारा सफर के दौरान यात्रियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता और साफ-सफाई से लोगों को बड़ी निराशा होती है।

मेरा माननीय रेलवे मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि साफ-सुथरे और पौष्टिक खाने के लिए उचित नीति तथा ट्रेनों एवं स्टेशनों पर अनाधिकृत विक्रेताओं की मौजूदगी रोकने के लिए और रेलवे यात्रियों की शिकायतों का त्वरित निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाए। इस सम्बन्ध में भारत के रेलवे स्टेशनों के आस पास जो भी गांवों की स्वयं सेवी महिलाओं की संस्था या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क करके, रेलवे मे पौष्टिक घर का खाना उपलब्ध कराने की योजनाओं की भी समीक्षा की जानी चाहिए, जिससे स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और यात्रिओं को पौष्टिक खाना भी मिल सकेगा।

मैं रेलवे मंत्रालय और सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): धन्यवाद, डा.सिकंदर कुमार जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यही संसद की खासियत होती है। सत्तारूढ़ दल भी, अगर कहीं कमजोरी है, तो सरकार से कहता है कि कृपया इसको ठीक करें। मैं प्रहलाद जोशी जी से कहूंगा कि आप माननीय रेलवे मिनिस्टर को अवगत कराएं कि जो मुद्दा डा. सिकंदर कुमार जी ने उठाया है। उन्होंने बताया है कि रेलवे में खराब खाना मिल रहा है, उसको दुरुस्त करना चाहिए और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। बहुत अच्छे, धन्यवाद।

The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by Dr. Sikander Kumar: Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Sanjeev Arora (Punjab), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar (Odisha) and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

Demand for establishment of five medical colleges of RAJMES (Rajasthan Medical Education Society) and MDRUs of Bharatpur, Bhilwara, Churu, Pali and Dungarpur

नीरज डांगी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, पाली एवं डूंगरपुर पांच राजमेस मेडिकल कॉलेजों के Multidisciplinary Research Unit (एमडीआरयू) की स्थापना के प्रस्ताव 14.08.2019 को भारत सरकार को प्रेषित किये गए।

राजस्थान सरकार द्वारा हस्ताक्षरयुक्त एमओयू दिनांक 28.11.2019 को प्रेषित किया। मेडिकल कॉलेजों से आए प्रस्तावों पर टेक्नीकल कमेटी से भीलवाड़ा तथा डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज हेतु ऑब्जरवेशन्स प्राप्त हुए हैं तथा भरतपुर, चूरू एवं पाली के लिये ऑब्जरवेशन्स प्राप्त होने शेष हैं। एमडीआरयू की डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज हेतु दिनांक 30.09.2021 को प्रथम किस्त 1.25 करोड रुपये की स्वीकृति, स्थान चिन्हित व पीडब्ल्यूडी को एजेंसी नियुक्त करने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

भीलवाड़ा हेतु पंजीकरण 21.09.2022 को पूर्ण किया। सीडीएससीओ, जीओएल से भारत सरकार के प्रश्नों के जवाब प्रतीक्षित है एवं भेजे गए संशोधित प्रस्तावों में भारत सरकार ने तीन आपत्तियां उठाई थीं। दो का समाधान हो चुका है और एक पशु आवास के संबंध में प्रक्रियाधीन है। पाली द्वारा 22.11.2022 एवं चूरू द्वारा 24.11.2022 को संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए गए। एमडीआरयू की पाली मेडिकल कॉलेज हेतु 27.3.2023 को 1.25 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त की स्वीकृति प्राप्त हुई, साइट चिह्नित की गई, एनएचएम को एजेंसी नियुक्त किया गया व उपकरण खरीद भी जल्द ही शुरू होगी। शेष पर भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.3.2023 के अनुसार चुरू के लिए संशोधित प्रस्ताव अग्रेषित किए जाने